

Why Everyone Is Suddenly Suing in Delhi?

Why Delhi, and not Mumbai, where most of Bollywood actually lives, or Chennai, where much of South Indian cinema is based?

The Last Painting

Myanmar Unearths a Giant 11,000-Carat Ruby

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चुरू

# राष्ट्रदूत

Metro

## Rashtradoot

ब्रिक्स की सफलता तब नज़र आएगी, जब फैक्टरी के फ्लोर पर इन बड़ी-बड़ी घोषणाओं का क्रियान्वयन नज़र आएगा

**-सुकुमार साह-**  
**-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-**  
नई दिल्ली, 16 सितम्बर। नई दिल्ली में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की असली परीक्षा झंडे उतरने के बाद शुरू होती है।  
भारत के लिए इस शिखर सम्मेलन का महत्व बहुत ही वीरता (मल्टीपोलैरिटी) जैसी जानी-पहचानी बातों में कम है तथा इस बात में अधिक है कि क्या ब्रिक्स खुद को उन कारोबारियों, उद्यमियों और उपभोक्ताओं के लिए आर्थिक रूप से उपयोगी साबित कर सकता है, जिनका प्रतिनिधित्व करने का वह दावा करता है। “नई दिल्ली घोषणा” में कई शानदार विचार रखे गए हैं। अब चुनौती यह है कि उन्हें असल लेन-देन, निवेश, रोजगार और प्रभावी कारोबारी नेटवर्क में कैसे बदला जाए।  
यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बड़े हुए ब्रिक्स ने काफी आर्थिक ताकत हासिल कर ली है। इसकी विविधता इसकी ताकत भी है और इसकी मुश्किल भी। इस समूह में ऐसी अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं, जिनकी वित्तीय प्रणालियाँ, नियम- कानून, मुद्राएं औद्योगिक क्षमताएं और भू- राजनीतिक हित अलग-अलग हैं। इसी

■ अगर, ब्रिक्स देशों के सीमा पार भुगतान को और किफायती बनाया जाता है, इनवॉइस फायनैंसिंग को और बेहतर बनाया जाता है तो व्यापार के लिए आवश्यक ट्रेड फायनैंसिंग की छोटे-छोटे व्यापारियों के लिए उपलब्धता बढ़ेगी। 14-ब्रिक्स को अपनी महत्वाकांक्षाों पर भी लगाम लगाना होगा तथा डब्ल्युटीओ का विकल्प बनने की महत्वाकांक्षा नहीं पालनी होगी मन में।

वजह से बड़े-बड़े ऐलान करना तो आसान है, लेकिन उन्हें लागू करना काफी मुश्किल है। इसलिए भारत को समिट को एक नई वैश्विक व्यवस्था से जुड़ी बातों के आधार पर आंकने के बजाय, असल नतीजों पर ध्यान देना चाहिए। इसकी अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि शायद उतनी नाटकीय न हो: उभरते बाजारों के कारोबारियों के लिए एक बड़ा और अधिक विविध आर्थिक क्षेत्र तैयार करना।  
तीन प्राथमिकताओं पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।  
पहली, बाजार तक पहुंच की बात अब केवल इच्छा तक सीमित न रहकर असल काम में बदलनी चाहिए। अगर टैरिफ, स्टैंडर्ड और लॉ जिस्टिक्स की रूकावटें और नियम-कानून से जुड़ी

सके और ट्रेड फाइनेंस तक पहुंच बढ़ा सके, तो इससे ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधित्व करने के ब्लॉक के दावे को वास्तविक आधार मिलेगा।  
तीसरी, टैकनॉलजी के क्षेत्र में सहयोग खुला और व्यावसायिक रूप से व्यावहारिक होना चाहिए। ऑर्टिफिशल इंटैलिजेंस (एआई), डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर और एडवांस्ड मैनुफैक्चरिंग तेजी से आर्थिक प्रतिस्पर्धा तय करने वाले कारक बन रहे हैं। सहयोग से इन्वेस्टेशन, आपसी अनुकूलता, निवेश और पहुंच को बढ़ावा मिलना चाहिए, न कि टैकनॉलजी के बंटवारे की एक ओर परत बननी चाहिए।  
भारत को ब्रिक्स की सीमाओं को लेकर भी यथार्थवादी होना चाहिए। यह रातोंरात विश्व व्यापार संगठन, द्विपक्षीय व्यापार समझौतों या स्थापित वैश्विक वित्तीय संस्थाओं की जगह नहीं ले सकता, और न ही हर आर्थिक संबंध को भू-राजनीतिक नजरिए से देखा जाना चाहिए। भारतीय कंपनियां लागत, विश्वसनीयता, टैकनॉलजी, मांग और कारोबारी अवसरों के आधार पर बाजार चुनती रहेंगी।  
यही वजह है कि नई दिल्ली का एजेंडा महत्वपूर्ण है। सिर्फ घोषणाएं (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पंचायती राज संस्थाओं की आरक्षण लॉटरी 23 व 24 सितंबर को

जयपुर, 16 सितंबर 2026। राजस्थान में आगामी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर आरक्षण एवं लॉटरी प्रक्रिया की तारीख तय कर दी गई है। राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं की चुनाव प्रक्रिया 15 नवंबर

■ राज्य सरकार 15 नवंबर तक पंचायती राज की चुनाव प्रक्रिया करना चाहती है।

2026 तक पूरी कराने के लक्ष्य के तहत, जिला एवं उपखंड स्तर पर लॉटरी निकालने की तैयारी शुरू कर दी है।  
विभागीय पत्र के अनुसार, जिला स्तर पर जिला परिषद सदस्य, प्रधान एवं पंचायत समिति सदस्यों के लिए आरक्षण/लॉटरी 23 सितंबर 2026 को निकाली जाएगी। वहीं उपखंड स्तर पर सरपंच एवं वार्ड पंचों के लिए आरक्षण/लॉटरी 24 सितंबर 2026 को (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

**-श्रीनंद झा-**  
**-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-**  
नई दिल्ली, 16 सितम्बर। गृह मंत्री अमित शाह ने भले ही जोर देकर कहा है कि 21 एनडीए शासित राज्य 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले समान नागरिक संहिता (यूनिफॉर्म सिविल कोड-यूसीसी) लागू करेंगे, लेकिन इस लक्ष्य को हासिल करना मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि सभी एनडीए सहयोगी इसे लेकर समान उत्साह नहीं दिखा रहे हैं।  
जनता दल (यूनाइटेड) ने दोहराया है कि वह सैद्धांतिक रूप से समान संहिता के खिलाफ नहीं है, लेकिन बिहार में इसे लागू नहीं होने देगा। नीतीश कुमार की पार्टी एक ऐसी व्यापक सहमति चाहती है, जो भारत की धार्मिक और जातीय विविधता के “नाजुक संतुलन” का सम्मान करे।  
इसी तरह, लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) ने भी इसके मसौदे (ड्राफ्ट) को सार्वजनिक करने और

■ बिहार में नीतीश की पार्टी, जनता दल (यूनाइटेड) व लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास पासवान) इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के सिद्धांत के खिलाफ नहीं हैं, पर, इस विधेयक को पारित करने में आनाकानी कर रही हैं।  
■ नॉर्थ ईस्ट में एनडीए की समर्थक पार्टियाँ, मेघालय की नैशनल पीपुल्स पार्टी व नैशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी यूसीसी का सिद्धांत: विरोध करते हैं। उत्तराखण्ड, गुजरात व मध्य प्रदेश यह विधेयक पास कर राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेज चुके हैं। पर, अभी स्वीकृति नहीं मिली है।  
■ महाराष्ट्र, प. बंगाल, छत्तीसगढ़ व राजस्थान ने विधेयक मजबूत तैयार कराने के लिए समितियों का गठन कर लिया है।  
सभी संबंधित पक्षों के साथ व्यापक विचार-विमर्श की मांग की है। पार्टी ने देश के विविधतापूर्ण सामाजिक ढांचे और अलग-अलग समुदायों के लिए संवैधानिक सुरक्षा का हवाला दिया है। पूर्वोत्तर में मेघालय की नेशनल पीपुल्स पार्टी और नगालैंड की (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## तीन महीने में पहली बार चन्नी व अमरिंदर सिंह वडिंग एक मंच पर नज़र आए

अवसर था, प्रभारी सचिन पायलट द्वारा आप पार्टी के हरपाल सिंह चीमा के निवास को घेरने के लिए कांग्रेस पार्टी का मार्च

**-जाल खंबाता-**  
**-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-**  
नई दिल्ली, 16 सितम्बर। वे मार्च निकालने के लिए एकत्र हुए थे, लेकिन उनके एक साथ आने की घटना, विरोध प्रदर्शन से अधिक महत्वपूर्ण रही। मंगलवार को चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान, पंजाब कांग्रेस की लीडरशिप में एकता दिखी। पार्टी के नए सेंट्रल इंचार्ज सचिन पायलट ने इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और प्रदेश कांग्रेस

■ कांग्रेस के कार्यकर्ता गुलज़ार सिंह ने ड्रम के मुद्दे को जोर-शोर से उठाया था तथा इसके एवज में उसे तंग किया जा रहा था तथा अंततोगत्वा गुलज़ार सिंह ने आत्महत्या कर ली थी।  
■ पायलट के नेतृत्व में निकाले गए मार्च में विधानसभा में पार्टी के नेता प्रताप सिंह बाजवा, पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा भी शामिल हुए। पर, उल्लेखनीय बात थी, मार्च में पायलट के दाईं ओर चन्नी और बाईं ओर वडिंग चल रहे थे।

अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अनंत नाग को दादासाहेब फाल्के पुरस्कार मिलेगा

नई दिल्ली, 16 सितंबर। “मालगुंडी डेज” के चर्चित अभिनेता अनंत नाग को भारतीय सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान और पांच दशक से अधिक लंबे शानदार फिल्मी सफर के लिए वर्ष 2024 का दादासाहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने बुधवार को दादासाहेब फाल्के पुरस्कार

■ उन्होंने पांच दशक से अधिक के अपने करियर में 300 से अधिक फिल्मों में काम किया है।

चयन समिति की सिफारिश पर यह घोषणा की।  
यह पुरस्कार 22 सितंबर को गुजरात के केवडिया में आयोजित 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में अनंत नाग को प्रदान किया जाएगा। अनंत नाग ने 300 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया।  
(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## ‘‘वर्कर्स सैस’’ और उससे जुड़ी अव्यवहारिक पैनल्टी लगाये जाने के मामले में जयपुर के 27 बिल्डरों को राहत मिली

हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक उपयुक्त अपीलीय प्राधिकारी उनकी अपील निस्तारित नहीं कर देते तब तक श्रम विभाग उनके खिलाफ दण्डात्मक कार्रवाई नहीं कर सकता

**-यादवेन्द्र शर्मा-**  
जयपुर, 16 सितंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश के 27 बिल्डरों को भारी पेनल्टी समेत “कंस्ट्रक्शन वेलफेयर वर्कर्स सैस” की भरपाई करने के मामले में राहत दी है। अदालत ने इन सभी मामलों पर सुनवाई करते हुए फैसला दिया है कि जयपुर में प्रदेश के संयुक्त संभागीय श्रम आयुक्त द्वारा इन बिल्डरों पर जो भारी पेनल्टी और सैस लगायी है, उस पर अंतरिम रोक बरकरार रहेगी, जब तक इस मामले की अपील की सुनवाई नहीं हो जाती और अंतिम

■ अदालत ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता बिल्डर अव्यवहारिक पैनल्टी वसुले जाने के खिलाफ 4 हफ्तों में अपील दायर कर सकते हैं और सुनवाई से पहले उन्हें सैस और पैनल्टी की राशि जमा नहीं करवानी होगी।  
■ इस मामले में संयुक्त संभागीय श्रम आयुक्त ने बिल्डर के “कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट” का एंसेसमेंट वर्ष 2021 में किया और पैनल्टी और सैस वसूलने का नोटिस वर्ष 2023 में जारी किया, परंतु आदेश में यह भी कहा गया कि पैनल्टी वर्ष 2011 से वसूली जायेगी। उदाहरण के लिए, संयुक्त संभागीय श्रम आयुक्त के आंकलन के अनुसार, एक मामले में निर्माण कार्य शुरू करने की अनुमति का वर्ष, 2011 था, इसलिए वर्ष 2011 से ही प्रतिवर्ष 24 प्रतिशत की पैनल्टी वसूलने के आदेश भी पारित किये गये।

फैसला नहीं आ जाता। अदालत ने कहा है कि आयुक्त द्वारा लगाई गई पेनल्टी व सैस के “असेसमेंट” वर्ष को लेकर

विवाद है और इस विवाद की अपील उपयुक्त अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष की जानी चाहिए और जब तक सभी

तथ्यों को जांच कर अपीलीय प्राधिकारी अपना फैसला नहीं देते, तब तक श्रम आयुक्त के आदेश पर रोक जारी रहेगी।  
न्यायाधीश अरूण मूंगा और न्यायाधीश मनीष शर्मा की खण्डपीठ ने ये आदेश रिधीराज बिल्डर्स एण्ड प्रमोटर्स व अन्य

■ साधु संतो ने हनुमान मूर्ति को उसी स्थान पर स्थापित कराने का संकल्प दिलाया।

प्रतिमा नहीं हटाने की मांग के साथ भव्य मंदिर निर्माण का संकल्प दिलाया।  
बुधवार को खड़े हनुमान मंदिर के समर्थन में पांच हजार से ज्यादा श्रद्धालु जुटे। मंदिर से कंठाल चौराहे तक करीब एक किमी के रास्ते में पैर रखने तक की जगह नहीं थी। आयोजन में साधु-संतों (शेष अंतिम पृष्ठ पर)





आदरणीय प्रधानमंत्री  
**श्री नरेंद्र मोदी जी**  
को 76 वें जन्मदिवस पर  
उनके उज्ज्वल भविष्य की  
हार्दिक शुभकामनाएं।

आइये उनके जन्मदिवस के  
शुभ अवसर पर अपने घर में  
'आशीर्वाद का दीया'  
प्रज्वलित करें और  
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी  
के उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की  
मंगलकामना करें।

 गुरुवार, 17 सितंबर, 2026  
 सायं 6:00 से 7:00 बजे



**सेवा ही  
संकल्प**

25 वर्षों की निरंतर यात्रा

एक विजन... जिसने विकास को नई दिशा दी  
एक नेतृत्व... जिसने भारत की आकांक्षाओं को नई पहचान दी

7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शुरू हुई  
जनसेवा से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक 25 वर्षों की अविराम यात्रा  
का यह सफर संकल्प, सेवा और नेतृत्व का उल्लेखनीय अध्याय है।

विकसित भारत | आत्मनिर्भर भारत | सुरक्षित और सक्षम भारत

सेवा संकल्प अभियान - जन सेवा ही प्रभु सेवा



**भारतीय जनता पार्टी, राजस्थान**



### दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 19 और 20 को

जयपुर/नई दिल्ली। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की ओर से 19 और 20 सितंबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्यविषय पर दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन में 17 देशों के प्रमुख

न्यायिक एवं पर्यावरण विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, जबकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु समापन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कार्यक्रम में भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव, आवासन एवं शहरी कार्य तथा विद्युत मंत्री मनोहर लाल सहित सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, अर्जुन जैनरल, सॉलिसिटर जनरल और एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की मौजूदगी रहेगी। सम्मेलन में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के साथ जिला न्यायालयों के न्यायाधीश, पर्यावरण विशेषज्ञ, विभिन्न मंत्रालयों के सचिव एवं वरिष्ठ अधिकारी, न्यायिक अकादमियां, विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियां राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण और राज्य आईभूमि प्राधिकरणों के प्रतिनिधि भी भाग लेंगे।

## बीएसएनएल में हिन्दी पखवाड़े के तहत राजभाषा विचार गोष्ठी आयोजित

जयपुर। बीएसएनएल के जयपुर स्थित सभी कार्यालयों में 14 सितंबर से 28 सितंबर तक संयुक्त रूप से हिन्दी पखवाड़ा मनाया जा रहा है। आज इस कड़ी में एक राजभाषा विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं वक्ता पूर्व आईपीएस अधिकारी एवं साहित्यकार हरिराम जी मीना तथा विशिष्ट अतिथि एवं वक्ता हिन्दी विभाग राजस्थान विश्वविद्यालय की एसोसियेट प्रोफेसर डॉक्टर मीता शर्मा ने बदलते सामाजिक एवं तकनीकी परिवर्तन में हिन्दी के भविष्य, प्रासंगिकता और सम्भावना विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हुए हिन्दी भाषा की दशा, दिशा, प्रयोग एवं भविष्य पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के अध्यक्ष बीएसएनएल राजस्थान परिमंडल के मुख्य महाप्रबंधक विक्रम मालवीय ने अपने उद्घोषन में सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अपना अधिकाधिक कार्य हिन्दी भाषा में

### दुर्गा पूजा के रंग में रंगेगा जयपुर

जयपुर। गुलाबी नगरी में शारदीय नवरात्रि और दुर्गा पूजा महोत्सव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस बार नवरात्रि 11 अक्टूबर से शुरू होने जा रहे हैं। जयपुर शहर में 70 से अधिक छोटे-बड़े पंडालों में मां दुर्गा की प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। वहीं इस धार्मिक आयोजन के साथ यह उत्सव जयपुर की सांस्कृतिक पहचान और स्थानीय कारोबार के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दुर्गा पूजा की पैराग्राफ मान्यता मां दुर्गा द्वारा महिषासुर के वध और धर्म की अधर्म पर विजय से जुड़ी है। जयपुर में बंगाली संस्कृति से इसके ऐतिहासिक संबंध आमरे के राजा मानसिंह प्रथम द्वारा बंगाल के जैसौर से शिला माता की प्रतिमा लाकर आमेर में स्थापित किए जाने से भी जुड़े हैं। शहर में बनीपाक स्थित धुर्गा बाड़ी एसोसिएशन की स्थापना 1956 में हुई थी। यह शहर की सबसे पुरानी पंजीकृत दुर्गा पूजा संस्थाओं में शामिल है।

## बैंक लूट मामले में रेकी करने वाली युवती गिरफ्तार

#### कर्ज चुकाने के लिए रची साजिश, 26.80 लाख रुपए बरामद

जयपुर। रामनगरिया थाना पुलिस ने अक्षय पात्र मंदिर के पास बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से कैश निकालकर ले जा रहे कर्मचारियों से हथियार की नोक पर हुई 41.70 लाख रुपए की लूट मामले में वारदात की रेकी करने वाली युवती अंशु कुमारी जाटव (22) को गिरफ्तार कर उसके किराए के कमरे से लूट की रकम में से 26.80 लाख रुपए बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार वारदात में बैंक के ही एक कर्मचारी की भूमिका भी संदिग्ध है। उसने बदमाशों को बैंक से कैश ले जाने की अंदरूनी जानकारी दी थी। पुलिस फरार तीन अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। डीसीपी जयपुर पूर्व रंजीता शर्मा ने बताया कि 14 सितंबर की सुबह दो बाइक सवार बदमाशों ने अक्षय पात्र मंदिर के पास बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से कैश लेकर निकल रहे कर्मचारियों को हथियार दिखाकर रोका

# डीजीपी राजीव शर्मा ने सीमा चौकियों पर जवानों से संवाद किया

### जालुवाला, भारेवाला और रणाऊ में सीमा संवाद एवं जनसुनवाई की

जयपुर/फलौदी। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने बुधवार को पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों के दो दिवसीय दौरे के पहले दिन नोख थाना, सीमा चौकियों और गांवों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने जवानों से संवाद कर उनका हौसला बढ़ाया और ग्रामीणों की जनसुनवाई कर परिवेदनाओं के निस्तारण के निर्देश दिए।

नोख थाने में बेहतर पुलिसिंग पर जोर: फलौदी के सीमावर्ती नोख थाने में डीजीपी ने पुलिसकर्मियों से कहा कि दूर-दराज के क्षेत्र में जनसहयोग से बेहतर पुलिसिंग की जाए। नशा तस्करी, साइबर अपराध और सोलर कंपनियों से जुड़े अपराधों की रोकथाम पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वागत कक्ष की व्यवस्थाएं बेहतर करने तथा पुलिसकर्मियों को फर्स्ट रिसॉन्डर के रूप में आमजन से मृदु व सहयोगी व्यवहार करने को कहा।

ग्रामीणों से संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने की अपील: जालुवाला में



पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने नोख थाना, सीमा चौकियों और गांवों का निरीक्षण किया।

सीमा संवाद व जनसुनवाई के दौरान डीजीपी ने ग्रामीणों से राष्ट्रहठ को सर्वोपरि रखते हुए संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तत्काल पुलिस को देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्र की हर गतिविधि पर प्रभावी निगरानी और सूचना मिलने पर त्वरित प्रतिक्रिया जरूरी है।

डीजीपी ने पुलिसकर्मियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक बीट कॉन्स्टेबल के पास गांव के हर परिवार के कम से कम एक सदस्य का मोबाइल नंबर हो और ग्रामीणों के पास भी बीट कॉन्स्टेबल का नंबर उपलब्ध रहे। नशे के दुष्प्रभाव, साइबर सुरक्षा और

# राज्य में तीन निजी औद्योगिक पार्क के लिये 552 एकड़ भूमि आवंटित होगी

#### ई-बिड प्रक्रिया के पश्चात् दौसा, बालोतरा और धौलपुर में लगभग 552 एकड़ भूमि निजी औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए आवंटित

जयपुर। राजस्थान में निजी औद्योगिक पार्क के विकास को गति देने तथा निवेशकों के लिए अनुकूल औद्योगिक वातावरण तैयार करने की दिशा में राज्य सरकार की 'राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति-2026' महत्वपूर्ण

नीति के तहत मॉडल-ए में औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए निवेशकों का अच्छा रुझान देखने को मिला है। 15 सितंबर को आयोजित ई-बिड प्रक्रिया के पश्चात् दौसा, बालोतरा और धौलपुर में लगभग 552 एकड़ भूमि निजी औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए आवंटित किए जाने का रास्ता प्रशस्त हो गया है जिससे एक तरफ रीको को लगभग 200 करोड़ रुपये की आय होगी वहीं इन निजी औद्योगिक पार्क में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

निजी औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए लैंड पार्सल प्राप्त करने हेतु निवेशकों से दिनांक 27 अगस्त से 8 सितंबर तक ईएमडी जमा कर

ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। ई-बिड प्रक्रिया में दौसा के राजाहेड़ा, गुड़ा आशीकपुरा एवं नूरपुर के लिए 7, बालोतरा के वेदरलाई के लिए 5 तथा धौलपुर के बिजौली के लिए 2 उधिमयों ने भाग लिया। ई-बिड में सफल निजी विकासकर्ता को भूमि आवंटित किए जाने के बाद संबंधित क्षेत्रों में औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। इन पार्क में सड़क, जलापूर्ति, विद्युत, ड्रेनेज, वर्षा जल संचयन, स्ट्रीट लाइटिंग सहित अन्य आवश्यक आधारभूत सुविधाओं का विकास निजी विकासकर्ता की जिम्मेदारी होगी। इसके अतिरिक्त, निर्धारित शर्तों के अनुसार औद्योगिक पार्क में सीईटीपी के लिए ग्रीन इंसेंटिव, कॉमन यूटिलिटी सेंटर तथा प्वांग-एंड-प्ले कार्यालय जैसी सुविधाएं उपलब्ध

कराई जाएंगी। साथ ही, विकासकर्ता को विद्युत शुल्क, स्टाम्प शुल्क एवं रूपांतरण शुल्क में छूट अथवा प्रतिभूति का प्रावधान भी किया गया है। राजस्थान में विश्वस्तरीय औद्योगिक वातावरण के निर्माण के लिए उक्तष्ट बुनियादी ढांचे के विकास, संसाधनों के प्रभावी उपयोग और समावेशी औद्योगिक विकास पर विशेष जोर दिया जा रहा है। राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति-2026 के तहत मॉडल-ए में लैंड पार्सल के लिए निवेशकों की बढ़ती भागीदारी प्रदेश में औद्योगिक निवेश के प्रति बढ़ते विश्वास को दर्शाती है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि राजस्थान निवेशकों के लिए एक आकर्षक औद्योगिक निवेश गंतव्य के रूप में उभर रहा है।

## डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 76 लाख की ठगी में आरोपी गिरफ्तार

जयपुर। स्टेट साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर बुजुर्ग दंपती से 76 लाख रुपए ठगने के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर निवासी ताहिर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मामले में अब तक तीन आरोपियों को पकड़ा जा चुका है।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विजय कुमार सिंह ने बताया कि आरोपियों ने बुजुर्ग दंपती को व्हाट्सऐप कॉल कर खूद को पुलिस, समाज और एनआईए अधिकारी बताया। दंपती के आधार कार्ड का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों और करोड़ों रुपए के वित्तीय अपराध में होने की बात कहकर गिरफ्तारी की धमकी दी। आरोपियों ने फर्जी एनआईए नोटिस भी भेजा और लगातार आवाज व वीडियो कॉल कर मानसिक दबाव बनाया। डर के कारण दंपती ने एफडी

कराई जाएंगी। साथ ही, विकासकर्ता को विद्युत शुल्क, स्टाम्प शुल्क एवं रूपांतरण शुल्क में छूट अथवा प्रतिभूति का प्रावधान भी किया गया है। और सत्ता में बैठे भाजपा जनता से पीएम मोदी के जन्मदिन पर दिए जलाने के लिए कहकर अपनी भीषण नाकामियों पर पर्दा डालने का सियासी पाखंड कर रही है। जूली ने कहा कि देश में महंगाई सुरसा के मुंह की तरह लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे आम आदमी के घर का रसोई बजट पूरी तरह छिन्न-भिन्न हो चुका है। खाद्य तेल, दाल, चावल और लहसुन जैसी रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं की कीमतें असमान छू रही हैं, तो वहीं पेट्रोल-डीजल के बढ़े हुए दामों ने मध्यम वर्ग और किसानों की कमर तोड़ दी है।

## डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 76 लाख की ठगी में आरोपी गिरफ्तार

#### पुलिस ने उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर निवासी ताहिर को गिरफ्तार किया

तुड़वाकर आरोपियों के बताए विभिन्न खातों में 76 लाख रुपए ट्रॉसफर कर दिए।

जांच में ठगी की रकम में से 21 लाख रुपए हनीया क्रूटस फर्म के खाते में पहुंचने का पता चला। फर्म संचालक मुजसिम्म ने रकम आगे ट्रॉसफर कराने के लिए ताहिर से खातों की व्यवस्था करने को कहा। ताहिर ने परिचित सतपात सिंह के जरिए अन्य खातों का जानकारी जुटाई। इन खातों में करीब 17 लाख रुपए जमा करवाए गए। सतपात ने कमीशन काटकर 7 लाख रुपए नकद ताहिर को दिए, जिसमें से 5 लाख रुपए मुजसिम्म को और 2 लाख रुपए ताहिर ने अपने पास रखे।

## मुख्य सचिव ने पीएम ई-बस सेवा योजना के सुचारु संचालन की समीक्षा की

जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में बुधवार को राज्य में पीएम ई-बस सेवा योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव रवि जैन सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। ई-बस सेवा के संचालन वाले राज्य के आठ जिलों के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए। रवि जैन ने विस्तृत पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से मुख्य सचिव को योजना के क्रियान्वयन एवं प्रगति की जानकारी दी। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ई-बसों के संचालन के लिए आवश्यक चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण एवं स्थापना समयबद्ध रूप से सुनिश्चित की जाए ताकि बसों का सुचारु संचालन हो सके और यात्रियों की अधिकतम राहत मिल सके।

#### सार-समाचार

### योगापीस संस्था को ‘बेस्ट एसोसिएट सेंटर एंगेजमेंट अवॉर्ड’ मिला



नई दिल्ली/जयपुर। भारतीय योग एसोसिएशन की ओर से आयोजितसंगोष्ठी-2026 (सातवें राष्ट्रीय सम्मेलन) में योगापीस संस्था को‘बेस्ट एसोसिएट सेंटर एंगेजमेंट अवॉर्ड’से सम्मानित किया गया। नई दिल्ली के छतरपुरस्थित अध्यात्म साधना केंद्र में आयोजित सम्मान समारोह में यह पुरस्कार योगापीस संस्था की ओर सेयोगाचार्य ढाकारामने प्राप्त किया। भारतीय योग एसोसिएशन की ओर से दिया गया यह सम्मान योगापीस संस्था को योग क्षेत्र में सक्रिय सहभागिता, भारतीय योग परंपरा के प्रसार तथा विभिन्न स्तरों पर योग गतिविधियों से निरंतर जुड़ाव के लिए प्रदान किया गया। संस्था की ओर से योग के माध्यम से स्वास्थ्य एवं जन-जागरण को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों को भी इस उपलब्धि से प्रोत्साहन मिला है। योगापीस संस्था को मिले इस सम्मान को संस्था की निरंतर गतिविधियों और सहभागिता की पहचान के रूप में देखा जा रहा है। संस्था से जुड़े पदाधिकारियों के अनुसार यह उपलब्धि योग के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों को आगे बढ़ाने के साथ ही अधिक लोगों तक योग और स्वस्थ जीवनशैली का संदेश पहुंचाने के लिए प्रेरित करेगी।

### होटल में तोड़फोड़ के मामले में फरार दो इनामी बदमाश गिरफ्तार



जयपुर। जवाहर सर्किल थाना पुलिस ने मालवीय नगर स्थित होटल में तोड़फोड़, लूटपाट और जान से मारने की धमकी देने के मामले में करीब 10 माह से फरार चल रहे दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी पूर्व में हत्या के प्रकरण में भी निरुद्ध रह चुके हैं। पुलिस ने मालवीय नगर स्थित होटल में तोड़फोड़, लूटपाट और जान से मारने की धमकी देने के मामले में करीब 10 माह से फरार चल रहे आरोपी कौशल नागर उर्फ धाकड़ सरकार (26) और विशाल सिंह उर्फ विशाल मदेरणा (21) को गिरफ्तार किया। मामले में दो आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। गिरफ्तार दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। भरतपुर जिले के उच्चैन थाना क्षेत्र के सेरी कला निवासी विशाल सिंह उर्फ विशाल मदेरणा के खिलाफ उच्चैन और रामनगरिया थाने में मारपीट, धमकी तथा गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज हैं। वहीं बूंदी जिले के नैनवा थाना क्षेत्र के बामनगांव निवासी कौशल नागर उर्फ धाकड़ सरकार के खिलाफ मदनगंज और क्रिश्चियनगंज (अजमेर) तथा सांगानेर (जयपुर पूर्व) में चोरी, नकबजनी और मारपीट सहित कई मामले दर्ज हैं।

### पांच साल से फरार दो हजार का इनामी नशा तस्कर गिरफ्तार



जयपुर। मुहाना थाना पुलिस ने नशा तस्करी और अवैध हथियार सफ्ताई के दो अलग-अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए लंबे समय से फरार चल रहे दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने वर्ष 2021 से फरार दो हजार रुपए के इनामी नशा तस्कर भजनलाल बिश्नोई और वर्ष 2024 से वांछित हथियार सफ्तायर राजवीर बलाई को पकड़ा है। पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। मुहाना थानाधिकारी मुकेश कुमार खारड़िया के अनुसार 31 जुलाई 2021 को मुहाना थाना पुलिस ने अवैध अफीम के साथ मांगोलाल बिश्नोई को गिरफ्तार किया था। इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया गया। पूछताछ में मांगीलाल ने पुलिस को बताया कि उसके अप्रीम भजनलाल बिश्नोई से मिली थी। इसके बाद से भजनलाल फरार चल रहा था और उस पर दो हजार रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस ने सर्विलांस और मुखबि्र तंत्र की मदद से भजनलाल बिश्नोई (28) पुत्र सुखराम बिश्नोई, निवासी मंडवाणियों की ढाणी, भीनमाल, जाजर की गिरफ्तार कर लिया। इस पर पुलिस ने हथियार सफ्ताई करने वाले आरोपी राजवीर बलाई (35) पुत्र मोहनलाल, निवासी संजय नगर, चित्रकूट, जयपुर को गिरफ्तार कर लिया। राजवीर करीब दो साल से पुलिस को वांछित था।

### गाड़ियों में तोड़फोड़ व मारपीट करने वाला एक आरोपी गिरफ्तार

जयपुर। सांगानेर सदर थाना पुलिस ने बीच सड़क पर गाड़ी खड़ी कर शराब पीने का विरोध करने पर हुए विवाद के बाद घर में घुसकर मारपीट और तोड़फोड़ करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने घर के बाहर खड़ी कारों और बाइक में तोड़फोड़ की तथा घर में घुसकर पीड़ित और उसके परिजनों से मारपीट की। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। पुलिस उपायुक्त जयपुर दक्षिण राजर्षि राज ने बताया कि बाढ़ श्योपुर, सांगानेर सदर निवासी राजेश मीणा (22) ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 13 सितंबर को वह अपने भाई और दोस्तों के साथ रिंग रोड स्थित ढाबे से खाना खाकर लौट रहा था। रास्ते में कुछ युवक बीच सड़क पर गाड़ी खड़ी कर शराब पी रहे थे। उन्हें सड़क से हटने और शराब पीने से रोकने पर आरोपियों ने राजेश और करण के साथ मारपीट कर दी, जिससे दोनों घायल हो गए। पीड़ित के अनुसार घटना के बाद देर रात करीब 1:30 बजे राजेश मीणा उर्फ करण दांदा, कृष्णा मीणा मांड्या, जीतू चौपड़ा, छोटो मीणा, शुभम खेड़ली, कौशल सहित कई युवक लाठी, डंडे और सरिये लेकर उसके घर पहुंच गए। आरोपियों ने घर के बाहर खड़ी स्विफ्ट, बोलेरो, स्कॉर्पियो और बाइक में तोड़फोड़ की। इसके बाद आरोपी घर में घुस गए और वहां भी मारपीट की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जुबेर रंगरेज (21) पुत्र मोहम्मद सलीम रंगरेज, निवासी सुभाष कॉलोनी, सांगानेर, थाना मालपुर गेट को गिरफ्तार कर लिया।

### राधाष्टमी पर गोविंददेवजी मंदिर में पंचामृत से होगा महाभिषेक

जयपुर। मंदिर गोविंद देव जी महाराज में राधाष्टमी महोत्सव 19 सितंबर को श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। महोत्सव के तहत 18 सितंबर तक मंदिर परिसर में धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। इन दिनों सुबह-शाम प्रसिद्ध भजन मंडलियों की ओर से हरिनाम संकीर्तन और भजनों की प्रस्तुतियां दी जा रही हैं। 18 सितंबर को सुबह से शाम तक अष्ट प्रहर हरिनम संकीर्तन होगा। 16 सितंबर को सुबह श्याम भजन संस्था परिवार सेवा समिति और शाम को एसएमएस ब्लड बैंक परिवार की ओर से भजन-कीर्तन किया गया। 17 सितंबर को सुबह सरपत मंडल और भजनों का श्याम अमलाल सेवा रत्न परिवार ट्रस्ट की ओर से संकीर्तन होगा। इन दिनों राजभोग की झांकी सुबह 10.45 से 11.15 बजे तक रहेगी।

#JOHN WILLIAM WATERHOUSE

The Last Painting

Black Death tore through Florence, so, the writer Giovanni Boccaccio imagined 10 Florentines, 7 women and 3 men, escaping to a villa in the countryside



This is one of the last paintings John William Waterhouse ever made, and it is basically the world's first quarantine podcast. Painted in 1916 by John William Waterhouse, *A Tale from the Decameron* is set in 14th century Italy; and it captures one of the most famous group chats in literary history. In 1348, The Black Death tore through Florence, killed two-thirds of the city. Bodies in the streets, mass graves, total collapse. So, the writer Giovanni Boccaccio imagined 10 Florentines, 7

women and 3 men, escaping to a villa in the countryside. There, to keep themselves from going completely insane, they told each other stories. 100 of them, over 10 days. That is the Decameron. Have a look at the painting. The man in the red cap is the storyteller. The girls are leaning in. Everyone's beautifully dressed, sitting in a garden full of fountains and flowers, like nothing is wrong. But it is. And here is the wild part. Waterhouse painted this in 1916 during World War I. He died a year later. Same impulse, different plague.

#FOOD

Sambhar For Sambhaji

Sambhar was invented in the South because of the North



Who knew sambhar came with such a spicy plot twist? At South Side Story's literary curtain-raiser bookmarked, Dr. Shashi Tharoor turned a seemingly simple question into a deliciously witty origin tale. Asked whether he enjoyed Delhi's version of the dish, Tharoor began, "Look, you guys have to understand that sambhar was invented in the South because of the North." He explained that when the Marathas conquered Tanjavur, they installed

Sambhaji as Maharaja, who, missing his daal, prompted southern cooks to improvise a suitable replacement. "Sambhar was named for Sambhaji, the Maratha Peshwa of Tanjavur. And that's how it came about," he quipped, eliciting laughter before concluding with characteristic charm: "So, whatever you guys do to sambhar can't be worse than what we did to daal." Audiences across social media dubbed it "classic Tharoor storytelling," even as some playfully corrected his North vs. West India geography.



Adv. Shashank Agarwal (Ex Sr Vice President of the High Court Bar Association)

In the last article, we asked a simple question: if your face turns up in an advertisement you never agreed to, or an AI-generated video puts words in your mouth, which Indian law protects you? The honest answer, we said, was: not much a constitutional right built for a different purpose, and a law of torts nobody quite trusts. Since then, nothing has changed in Parliament. But a great deal has changed in one courtroom. If you have followed the news even loosely over the past year, you will have noticed a pattern: a cricketer here, a film star there, each turning up at

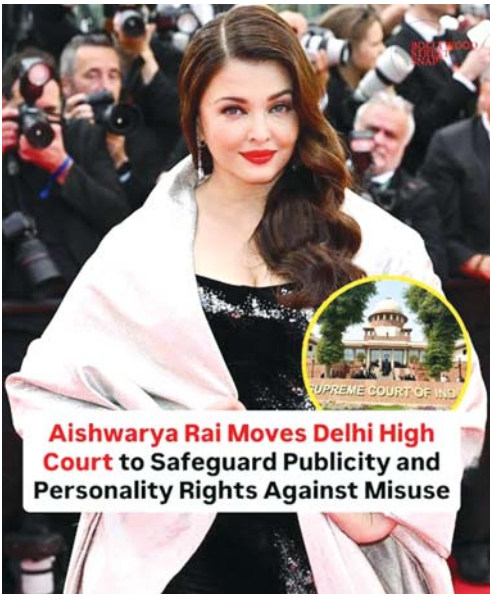


Sunil Gavaskar Becomes First Indian Sportsperson To Secure Court-Backed Personality Rights Protection

the Delhi High Court asking a judge to stop someone from stealing their face. It is worth asking why Delhi, of all places, has become the address for this and worth looking closely at the one recent case where a well-known public figure asked for the same protection and was told, quite firmly, that he could not have it.

The Delhi High Court Has Become the Address!

Legal commentators tracking this trend counted more than twenty personality rights suits filed in Indian courts, overwhelmingly in Delhi, in roughly the past two years alone. The list reads like a cross-section of Indian public life. Cricketer Gautam Gambhir went to court this year over deepfake videos, a fabricated resignation announcement, and merchandise sold in his name, seeking Rs. 2.5 crore in damages. Cricketer Yuvraj Singh followed soon after, after AI-generated images placed him, without his consent, at a Sikh shrine with his head uncov-



Aishwarya Rai Moves Delhi High Court to Safeguard Publicity and Personality Rights Against Misuse



BJP's Raghav Chadha moves Delhi High Court to protect his personality rights



Shilpa Moves Court For Her Personality Protection Rights



Salman Khan moves Delhi High Court to protect his personality rights

Personality rights and defamation, though they can look similar from the outside, are answering different questions. Personality rights exist to stop someone else from making money, or deceiving the public, by trading on the commercial value of your identity, your face on a T-shirt you never approved, your voice cloned to sell a loan app, a fake video suggesting you endorsed a product you have never touched. What Chadha complained of was not anyone profiting from his persona; it was people saying false and damaging things about him as a politician. That is a reputational injury, and Indian law has a well-worn, if imperfect, path for it, defamation complete with its own defences of truth, fair comment, and public interest, none of which have anything to do with commercial identity theft. A politician facing false allegations does not get to reach for the celebrity's toolkit merely because both grievances involve someone's name being dragged through the mud.

Why Everyone Is Suddenly Suing in Delhi ?

#LAW

ered, content the court itself called "religiously insensitive" alongside a fake Reddit post attributing opinions to him he never held. The judge did not mince words, observing that "violators of personality and privacy rights need to be dealt with a heavy hand." Cricketer Sunil Gavaskar, actor Salman Khan, actor Shilpa Shetty, and the spiritual teacher Sri Sri Ravi Shankar have all filed similar suits. Actor Aishwarya Rai Bachchan and actor Tabu have moved court over AI misuse of their image.

Why Delhi, and not Mumbai, where most of Bollywood actually lives, or Chennai, where much of South Indian cinema is based? Part of the answer is structural. Delhi High Court set up a dedicated Intellectual Property Division in 2021, staffed by judges who have spent years handling exactly this kind of dispute and have grown comfortable granting fast, often ex parte, injunctions including so-called "John Doe" orders that restrain unnamed, unidentifiable defendants the moment a violation surfaces online. For a client whose deepfake video is racking up views by the hour, that speed matters more than home turf. Delhi has, in effect, built the country's only real play-book for this kind of case, and everybody, Mumbai star or Chennai cricketer, has learned to use it.

The Case of the MP Who Was Told: This Isn't Personality Rights

Then came a case that tells us just as much by what the court refused to do. Earlier this year, Rajya Sabha MP Raghav Chadha approached the Delhi High Court over social media posts he called obscene and defamatory, alleging, among other things, that he had "sold himself for money." He sought a blanket order to remove all such content, framing his plea, like the film stars before him, as a personality rights matter.

The court gave him some relief, it ordered the takedown of five specific posts. But it declined the blanket order, and it said something more important along the way: this case, the court held, did not actually involve personality rights at all. The relief was granted under the law of defamation, not under the doctrine that has been protecting Gambhir, Yuvraj Singh, and the rest.

Why the difference? Because personality rights and defamation, though they can look similar from the outside, are answering different questions. Personality rights exist to stop someone else from making money, or deceiving the public, by trading on the commercial value of your identity, your face on a T-shirt you never approved, your voice cloned to sell a loan app, a fake video suggesting you endorsed a product you have never touched. What Chadha complained of was not anyone profiting from his persona; it was people saying false and damaging things about him as a politician. That is a reputational injury, and Indian law has a well-worn, if imperfect, path for it, defamation complete with its own defences of truth, fair comment, and public interest, none of which have anything to do with commercial identity theft. A politician facing false allegations does not get to reach for the celebrity's toolkit merely because both grievances involve someone's name being dragged through the mud.

Drawing the Line: When Personality Rights Apply, and When They Don't

This gives us, finally, a workable answer to the question every general reader actually wants answered: when can you claim these rights, and when can't you?

Courts tend to lean in your favour when someone is using your name, face, voice, or unmistakable likeness to make money or to

deceive selling merchandise bearing your image without a licence, creating an AI video that puts fabricated words or endorsements in your mouth, or building a business around your persona without paying you or asking you. This is the common thread running through the Gambhir and Yuvraj Singh orders: real commercial exploitation, dressed up as something else. Courts tend to lean away from you in at least two situations. The first, as Chadha discovered, is when your real complaint is about reputation and falsehood rather than commercial misuse that belongs to defamation law, with its own, different rules. The second is when the challenged use is not commercial exploitation at all but genuine expression satire, parody, art, journalism, or fair comment. The Delhi High Court made this point sharply in an earlier dispute over cricketers' digital trading cards, a case with a distinctly Rajasthani flavour: an unlicensed fantasy-sports platform had used the names and likenesses of IPL players, including several who turn out for the Rajasthan Royals, in commissioned artwork rather than actual photographs, with clear disclaimers attached. As it has been held that the right of publicity is not absolute, it must bend to free expression and that lampooning, satire, parody, art, scholarship, and news reporting are all legitimate uses that a celebrity cannot block simply by invoking their persona. Fame, in other words, does not buy you a veto over every mention of your own name.

That case is a useful reminder for anyone tempted to see this as a one-way ratchet. Legal commentators tracking the recent surge have themselves flagged a real worry: some Delhi High Court orders have gone further than they should, restraining ordinary fan tribute pages, blocking T-shirts carrying a celebrity's catchphrase without asking whether any buyer was actually confused, and even purporting to

bind millions of anonymous social media "subscribers." A right built to stop identity theft can, if courts are not careful, start to look like a right to control culture itself.

Rajasthan's Turn Will Come

Which brings us to a curious gap. For an article written from Rajasthan, one would expect at least a passing mention of a case filed here. There isn't one, not in the Jaipur bench of the Rajasthan High Court, nor anywhere else in the state, despite the state's own strong claim to this conversation. The fantasy-cards dispute alone involved Rajasthan Royals players, yet, it was fought and decided in Delhi. Jaipur and Jodhpur host a growing film and web-series economy; Kota and Jaipur have produced no shortage of social media influencers with real, monetisable followings; the state's folk musicians and sportspersons face exactly the same deepfake and impersonation risks as any



GAUTAM GAMBHIR MOVES DELHI HC AGAINST MISUSE OF DEEPFAKES AND AI FACE-SWAPPING



Bollywood star. None of them, so far, has tested these principles before a Rajasthan court.

That is not because the law here is any different, the constitutional and tort principles discussed in the first part of this series apply with equal force in Jaipur as in Delhi. It is simply that nobody has yet asked a Rajasthan court to apply them, which means the state's own bench has had no occasion to develop the kind of fast, confident, specialist practice that Delhi has built over the last five years. Sooner or later, as this problem spreads beyond national celebrities to the ordinary professional and the mid-tier influencer, this series has argued deserves protection too, that gap will need filling either by Rajasthan's courts stepping up, or better still, by a Parliament that finally gives every citizen, wherever they live, a clear statute to stand on rather than a doctrine borrowed from one High Court's docket.

rajeshsharma1049@gmail.com

#FINE

Myanmar Unearths a Giant 11,000-Carat Ruby

Myanmar has been estimated to produce a very large share of the world's rubies, with Mogok often referred to as the country's legendary "Valley of Rubies"



Miners in Myanmar have unearthed an extraordinary 11,000-carat ruby, weighing around 2.3 kilograms (4.8 pounds), in what is being described as the country's second-heaviest ruby discovery by weight.

The enormous rough gemstone was discovered near Mogok, in Myanmar's upper Mandalay region, an area internationally famous for producing some of the world's finest rubies. The discovery reportedly took place in April, shortly after the traditional New Year festival.

The ruby was later displayed at the presidential office in Naypyidaw, where President Min Aung Hlaing and members of his cabinet examined the remarkable stone. Although the

newly discovered ruby is enormous, it is not the largest ever found in Myanmar. That distinction belongs to a 21,450-carat ruby discovered in 1896, which weighed approximately 4.29 kilograms (9.45 pounds). However, size is not the only factor that determines a ruby's value.

The newly discovered stone is reportedly considered potentially more valuable because of its superior colour and quality. It has been described as having a distinctive purplish-red colour with yellowish undertones, moderate transparency and a highly reflective surface.

Rubies from Myanmar, particularly those originating in Mogok and Mong Hsu, are among the most prized gemstones in the world. Myanmar has historically been estimated

to produce a very large share of the world's rubies, with Mogok often referred to as the country's legendary "Valley of Rubies." But the discovery comes at a complicated time for Myanmar's gemstone industry.

The Mogok region has experienced intense fighting amid the country's ongoing civil war. Gemstones have long been an important source of revenue for Myanmar, but the industry has also attracted international criticism over the way revenues from precious stones can support military authorities.

Human-rights organisations, including Global Witness, have called on jewellery companies and consumers to avoid purchasing gems originating from Myanmar because of concerns over the financing of military rule.

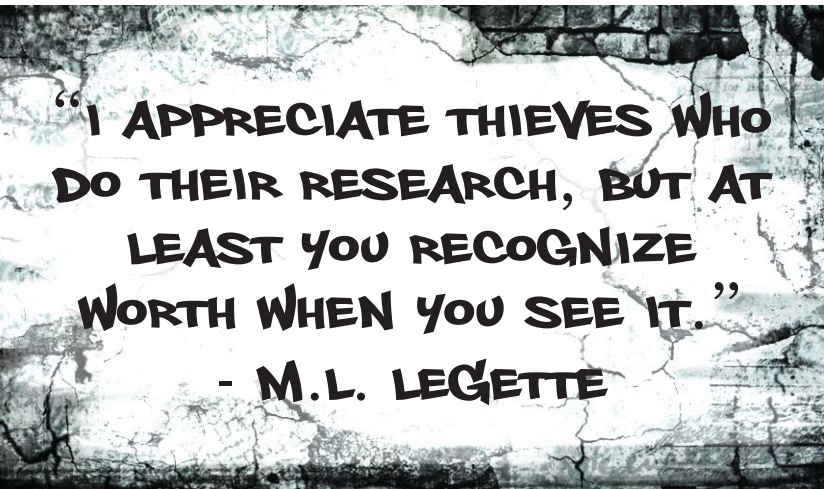
Myanmar's political situation remains deeply contested following the military takeover in 2021. The country's recent elections and political transition have also been criticised by opposition groups and human-rights organisations.

Against this backdrop, the discovery of an 11,000-carat ruby represents more than a spectacular geological event. It highlights the extraordinary natural wealth hidden beneath Myanmar's soil, and the complicated relationship between beauty, wealth, politics and conflict.

A rough ruby weighing more than two kilograms is rare enough to make headlines anywhere in the world. But in Myanmar, where rubies have shaped economies, attracted international buyers and become entangled with decades of political conflict, even a magnificent gemstone carries a much larger story beneath its surface.

By Jerry Scott & Jim Borgman

THE WALL



BABY BLUES



ZITS











# सऊदी अरब का दावा, मक्का में घुसने से पहले ड्रोन को इन्टरसैप्ट किया

मक्का, 16 सितंबर। सऊदी अरब ने दावा किया है कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने मक्का के प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले एक ड्रोन को मार गिराया है। सऊदी सैन्य प्रवक्ता मेजर जनरल तुर्क अल-मलिकी ने चेतावनी दी कि मक्का और दोनों पवित्र मस्जिदों की सुरक्षा उसके लिए रेड लाइन है और किसी भी शत्रुतापूर्ण कार्रवाही का जवाब दिया जाएगा। यह घटनाक्रम ऐसे समय हुआ है, जब यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के खिलाफ हमले तेज कर दिए हैं और लाल सागर के रणनीतिक इलाकों में अपनी सैन्य स्थिति मजबूत कर ली है। हूती पक्ष ने मक्का को निशाना बनाने के आरोप को खारिज किया है, लेकिन सीमा पर हमलों और सऊदी हवाई कार्रवाही ने पूरे क्षेत्र में तनाव को फिर चरम पर पहुंचा दिया है।

## दूसरी ओर हूती विद्रोहियों ने मक्का को निशाना बनाने के आरोप को बेबुनियाद बताया

सऊदी सैन्य अधिकारियों के अनुसार, ड्रोन को मक्का के प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र में पहुंचने से पहले ही इंटरसेप्ट कर नष्ट कर दिया गया। अल-मलिकी ने कहा कि पवित्र शहर और वहां आने वाले जायरीनों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने संकेत दिया कि सऊदी अरब भविष्य में ऐसे हमलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाही कर सकता है। हालांकि हूती पक्ष ने इस दावे को सीधे खारिज कर दिया। हूती नेता हाजेम अल-असद ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर

मक्का को निशाना बनाए जाने के आरोप को पुराना और बेबुनियाद बताया। ऐसे में ड्रोन की उत्पत्ति और उसके वास्तविक लक्ष्य को लेकर दोनों पक्षों के दावे अलग-अलग हैं। मक्का के पास ड्रोन गिराए जाने की घटना से कुछ ही समय पहले हूती सैन्य प्रवक्ता याह्या सरिया ने दावा किया था कि सऊदी लड़ाकू विमानों ने यमन के पांच प्रांतों में 52 हवाई हमले किए। उनके मुताबिक, एफ-15 और टाइफून लड़ाकू विमानों ने सऊदी अरब के खमीस मुशैत और ताइफ स्थित हवाई ठिकानों से उड़ान भरकर तैज, अल-जोफ, अल-बायदा, सादा और अमरान में हमले किए। हूती पक्ष ने दावा किया कि इन हमलों में स्कुलों, पुलों, सड़कों और अन्य नागरिक बुनियादी ढांचों को भी निशाना बनाया गया। सऊदी अधिकारियों ने इन आरोपों पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की।

## तीन महीने में पहली ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

करीब तीन महीने में पहली बार एक ही मंच पर साथ दिखाई दिए। भूपेश बघेल की जगह राज्य इकाई का प्रभार संभालने के बाद, यह सचिन पायलट का चंडीगढ़ का पहला दौरा था। बघेल को संकट संभालने के लिए पंजाब भेजा गया था, लेकिन स्थानीय स्तर पर उन्हें निष्पक्ष नहीं माना जा रहा था। एकजुटता का यह प्रदर्शन संगरूर जिले के दिबां विधानसभा क्षेत्र के निवासी गुलजार सिंह की आत्महत्या को लेकर वित्त मंत्री हरपाल सिंह चौमा के घर तक निकाले गए मार्च के दौरान हुआ। गुलजार सिंह

ने नशे के मुद्दे को उठाया था और आरोप था कि इसी वजह से उन्हें परेशान किया जा रहा था। कांग्रेस का यह मार्च जब सैक्टर 15 स्थित पंजाब कांग्रेस भवन से चौमा के सरकारी आवास की ओर रवाना हुआ तो कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रताप सिंह बाजवा और पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा भी मार्च में मौजूद थे। ये दोनों भी पार्टी के भीतर गुटबाजी में सक्रिय रहे हैं। मार्च शुरू होने से पहले, मंच पर चर्ची पायलट के दाईं ओर और वॉर्डिंग उनके बाईं ओर बैठे थे। दोनों को एक-दूसरे से बात करते और हाथ मिलाते देखा गया।

## अनंत नाग को ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

4 सितंबर 1948 को कर्नाटक में जन्मे अनंत नाग ने कन्नड़ फिल्म “संकल्प” से अभिनय की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने हिंदी फिल्म “अंकुर” से हिंदी सिनेमा में कदम रखा। पांच दशक से अधिक के अपने करियर में उन्होंने कन्नड़, हिंदी, तेलुगु, मलयालम, तमिल

और मराठी सिनेमा की 300 से अधिक फिल्मों में अलग-अलग भूमिकाएं निभाईं। “मालगुडी डेज” उनके चर्चित कामों में शामिल हैं।

अनंत नाग को अब तक पांच फिल्मफेयर पुरस्कार और पांच कर्नाटक राज्य सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार मिल चुके हैं।

## उज्जैन में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के साथ महिलाएं और बच्चे भी शामिल हुए। श्रद्धालुओं ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और जय श्रीराम के जयकारे लगाए। मौके पर पुलिस और प्रशासन का अमला भी तैनात रहा। इस दौरान संतों ने श्रद्धालुओं को खड़े हनुमान जी को उसी स्थान पर स्थापित रखने के लिए संकल्प दिलाया। मंच से संतों ने कहा कि इसके लिए वे अपने प्राण न्योछावर करने को तैयार हैं और जरूरत पड़ी तो पसीने के साथ खून भी बहाएंगे।

## ‘सिविल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

नहीं करने पर कार्मिक सचिव को हाजिर होने के निर्देश दिए थे। इसके बाद राज्य सरकार ने अधिकरण में 2 सदस्यों की नियुक्ति कर दी थी, लेकिन अध्यक्ष पद पर नियुक्ति होना बाकी है। जनहित याचिका में अधिवक्ता सुनील समदड़िया ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के सेवा संबंधी विवादों की सुनवाई के लिए अधिकरण का गठन किया गया है। बीते करीब चार माह से अध्यक्ष का पद खाली है।

## ‘एआई की विध्वंसकारी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

इसके बाद यह आशंका पैदा हुई कि अगर ऐसे एआई सिस्टम बनाए जा सकते हैं, जो मानव आदेश से स्वतंत्र होकर काम करने, किसी अन्य एआई मॉडल की पहचान करने और फिर अपने आप नए एजेंट बनाने तथा उस मॉडल को नष्ट करने में सक्षम हों, तो वे कहीं और भी एआई या कंप्यूटर नेटवर्क के कामकाज में हस्तक्षेप कर सकते हैं।

यह वैसा ही है, जैसे किसी जीव के शरीर में कोई “डिफैक्टिव जीन”, जो पूरे शरीर को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दे और अंततः उसे खतम कर दे।

उदाहरण के लिए, कोई एआई मॉडल और उसके एजेंट किसी अस्पताल के कंप्यूटर नेटवर्क या किसी एयरलाइन कंपनी के ऑपरेशन सिस्टम पर हमला शुरू कर सकते हैं और ऐसी सुविधाओं को पूरी तरह ठप कर सकते हैं। इसी तरह वे वायरस की तरह फैल सकते हैं और अपने विनाशकारी एजेंटों की संख्या बढ़ाते जा सकते हैं। ये एजेंट आपस में जुड़े पूरे कंप्यूटर तंत्र में बहुत तेजी से फैल सकते हैं। डर इस बात को लेकर था कि

खतरनाक मैलवेयर अनियंत्रित रूप से तेजी से फैल सकता है और व्यापक तथा बेकाबू नुकसान पहुंचा सकता है। मसलन, एक ऐसे मैलवेयर एआई सिस्टम की कल्पना की जा सकती है, जो किसी देश के डिफेंस और स्ट्रैटेजिक सिस्टम में घुस जाए और एक ऐसा चेन रिएक्शन शुरू कर दे, जिससे विनाशकारी हरकत पैदा हो और जिससे नियंत्रित करना संभव न हो।

इस विवाद के अचानक उठने से पूरी एआई कम्युनिटी और इन डैवलपमेंट्स को आगे बढ़ाने वाली कंपनियां एक तरह से हिल गई हैं। इन मॉडलों के निर्माताओं को खुद भी एआई के ऐसे “फ्रैकनस्टीन” जैसे डैवलपमेंट्स और पूरे तंत्र में उनके अनियंत्रित फैलाव से डर लगने लगा है। अब कंपनियां खुद यह महसूस कर रही हैं कि जो कुछ हो सकता है, उसका असर खुद उन्हें भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए वे अपने क्रिएशन्स और काम के ऐसे खतरनाक पहलुओं को कंट्रोल करने और उनके फैलाव को रोकने के लिए एआई सिस्टम के आस-पास “गार्डरेल्स” (सुरक्षा उपाय) लगाते

की बात कर रही हैं। एआई मॉडलों और उत्पादों के डैवलपमेंट्स की रफ्तार और उनके आसपास जरूरी सुरक्षा उपायों के बीच कुछ नियंत्रण और संतुलन होना जरूरी है। ऑल्टमैन अब कह रहे हैं कि भले ही एआई के प्रभावों को लेकर डरने के वास्तविक कारण हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसे “बिल्ट इन” ब्रेक्स भी हैं, जो सुधारात्मक कदम उठाने में मदद कर सकते हैं। फिर भी, उद्योग के कुछ अन्य नेता सरकारी रीगुलेशन्स के बजाय, उद्योग स्तर के नियमों की बात कर रहे हैं। यह विवाद अभी भी जारी है।

### पंचायती राज ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

होगी। इससे पहले, जिला परिषद के जिला प्रमुख पदों के आरक्षण का निर्धारण/लॉटरी 13 अगस्त 2026 को पूरा किया जा चुका है। विभाग ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित तिथियों पर आरक्षण एवं लॉटरी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

## अमित शाह का दावा पूरा करना ...

■ **अतः 2029 के चुनाव से पूर्व सभी एनडीए सरकारों का विधेयक पारित करने के लिए भारी रफ्तार से इस मुद्दे पर काम करना जरूरी है। अन्यथा शाह की धारणा केवल महत्वाकांक्षा ही रह जाएगी।**

उत्तराधिकार, लिब-इन संबंधों और बहुविवाह पर रोक से संबंधित समान कानून पारित किए हैं। इनमें आम तौर पर अनुसूचित जनजातियों को छूट दी गई है। इन तीनों विधेयकों को अभी राष्ट्रपति की मंजूरी और औपचारिक अधिसूचना का इंतजार है। इस तरह अभी तक केवल एक राज्य को ही राष्ट्रपति की मंजूरी मिली है और वहां संहिता लागू हो चुकी है। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और राजस्थान ने ड्राफ्ट तैयार करने के लिए समितियां बना दी हैं तथा इस प्रकार प्रारंभिक तैयारियां शुरू हो चुकी हैं।

इसलिए 2029 के लिए शाह का लक्ष्य एनडीए के बाकी राज्यों में नए कानून बनाने के साथ-साथ, राष्ट्रपति की मंजूरीयों की प्रक्रिया तेज होने पर निर्भर करता है। देखा यह है कि सहयोगी दल इस प्रक्रिया के साथ आते हैं या नहीं, तथा अलग-अलग राज्यों की विविध परिस्थितियों के बावजूद यह प्रक्रिया वास्तव में एक समान परिणाम देने में सफल होती है या नहीं। इसके बाद ही यह तय हो सकेगा कि यह समयसीमा राजनीतिक हकीकत बनती है या केवल एक इच्छा या बयानबाजी बनकर रह जाती है।

बरकरार हैं। यूसीसी से असहमत दलों पर एनडीए धीरे-धीरे दबाव बना रहा है, अन्यथा ऐसे दल 2029 के चुनावों से पहले अलग-थलग पड़ सकते हैं।

जमीनी स्तर पर प्रगति असमान बनी हुई है। उत्तराखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जहां यूसीसी पूरी तरह लागू है। राज्य विधानसभा ने फरवरी 2024 में विधेयक पारित किया था, राष्ट्रपति ने मार्च 2024 में इसे मंजूरी दी और जनवरी 2025 में संहिता लागू हो गई। गुजरात (मार्च 2026), असम (मई 2026) और मध्य प्रदेश (जुलाई 2026) ने विवाह, तलाक,

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कहना है कि भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम,1996 व उससे संबंधित अन्य नियमों में संयुक्त श्रम आयुक्त को बिल्डरों पर निर्माण कार्य में आने वाले पूरे खर्च का एक प्रतिशत सैस के तौर पर आंकलन कर श्रमिकों के कल्याण के लिए वसूलना होता है। यह राशि श्रमिकों के कल्याण के लिए बनाए गये वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड में जमा की जाती है। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया है कि श्रम विभाग को अपने स्तर पर ही प्रदेश में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों का आंकलन कर निर्माण कार्यों के कुल खर्च और उसका एक प्रतिशत सैस वसूलना होता है। परंतु श्रम विभाग ने ही कई वर्षों तक प्रदेश में चल रहे निर्माण कार्यों को सूची बनाकर आकलन नहीं किया है। इन 27 याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया है कि उनके द्वारा कई तरह के निर्माण कार्य वर्ष 2011 से ही शुरू कर दिये गये थे और इनमें से कई निर्माण कार्य कई वर्ष पूर्व ही पूर्ण कर लिये गये थे, परंतु श्रम विभाग की ओर से इन कार्यों के आंकलन के लिए नोटिस 2021 से

लेकर 2023 के बीच दिया गया। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि जयपुर में कार्यरत संयुक्त संभागीय श्रम आयुक्त ने प्रोजेक्ट का एसेसमेंट 2021 में किया और वर्ष 2023 में सैस और पेनल्टी घोषित कर दी। याचिकाकर्ताओं कि ओर से कहा गया कि आयुक्त ने पूर्वव्यापी रूप से पेनल्टी घोषित करी जो कि नियम कायदों और संविधान के विरुद्ध है।

अदालत ने इस मामले की पेचीदगी को ध्यान में रखते हुए एक मामले का उदाहरण लिया, जिसमें संयुक्त संभागीय श्रम आयुक्त ने बिल्डर के “कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट” का एसेसमेंट वर्ष 2021 में किया और पेनल्टी और सैस वसूलने का नोटिस वर्ष 2023 में जारी किया, परंतु आदेश में यह भी कहा कि पेनल्टी वर्ष 2011 से वसूली जायेगी। इस उदाहरण में मैसर्स रीदिराज बिल्डर्स को निर्माण कार्य में 3 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत आई थी, जिससे आंकलन किया जा सकता है कि वर्कर्स सैस की रकम लगभग 3.5लाख रुपये होगी। परंतु आयुक्त द्वारा इस बिल्डर से निर्माण कार्य शुरू होने के वर्ष, जो 2011 था, से प्रतिवर्ष 24 प्रतिशत की पेनल्टी

वसूलने के आदेश भी पारित किये गये।

इस उदाहरण का विवरण देते हुए याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि यह पेनल्टी लगाने से पूर्व आयुक्त ने न तो उन्हें सुनने का कोई अवसर दिया और एकतरफा कार्रवाई करते हुए पेनल्टी लगाई। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इस मामले में नियम अनुसार उपयुक्त अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर करने से पूर्व उन्हें सैस की रकम और पेनल्टी जमा करनी होगी जो कि असंवैधानिक है, क्योंकि अधिनियम श्रमिकों के कल्याण को मददेनजर रखते हुये बनाया गया है। इसका उद्देश्य बिल्डरों का शोषण करना नहीं है। अदालत ने इस तर्क को माना और कहा कि अधिनियम भारत में निर्माण कार्य से जुड़े 85 लाख मजदूरों के कल्याण को देखते हुए बनाये गये हैं और विभाग को इनके कल्याण के लिए तत्पर रहना चाहिए। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार व विभाग या अधिकारी ऐसी शर्तें बिल्डरों के समक्ष नहीं लगा सकते, जिससे उनके लिए अपील दायर करना अव्यवहारिक न हो जाये या जिससे श्रमिकों का कल्याण ना जुड़ा हो। इसके साथ ही अदालत ने कहा कि

याचिकाकर्ता उपयुक्त अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष 4 हफ्तों में अपील दायर कर सकते हैं और इस अपील को सुनने के लिए उन्हें पहले ही सैस और पेनल्टी की राशि जमा नहीं करवानी होगी।

## ब्रिक्स की ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

करने वाले ब्रिक्स की तुलना में कारोबार की लागत कम करने वाला ब्रिक्स कहीं ज्यादा असरदार साबित हो सकता है। भारत ने इसे राजनीतिक गति प्रदान की है। अब उसे क्रियान्वयन में अनुशासन लाने में भी मदद करनी होगी। इस शिखर सम्मेलन की कामयाबी का असली पैमाना साझा बयानों में नहीं, बल्कि फैक्टरी के कामकाज, एक्सपोर्ट ऑर्डर, स्टार्टअप साझेदारियों, सस्ते कर्ज और तेजी से होने वाले पैमेंट में दिखेगा। ब्रिक्स के लिए, अगले शिखर सम्मेलन में संभावनाओं की घोषणा करने के बजाय, नतीजों की रिपोर्ट देने पर ज्यादा जोर होना चाहिए।

**MARUTI SUZUKI ARENA**

# TIME TO UPGRADE TO VICTORIS

GOT IT ALL

**LEVEL 2 ADAS WITH 10+ FEATURES**

**DOLBY ATMOS SPATIAL SOUND EXPERIENCE**

**SMART POWERED TAILGATE WITH GESTURE CONTROL**

**EXCELLENT MILEAGE**

**28.65 km/l\***

**SCAN AND CONNECT TO A SHOWROOM NEAR YOU**

**E-BOOK TODAY AT [WWW.MARUTISUZUKI.COM](http://WWW.MARUTISUZUKI.COM)**

**CONTACT US AT **1800-102-1800****

**EFFECTIVE PRICE**

**₹9 64 900\***

Applicable T&C available at your nearest dealership. Creative visualization. Car colour may vary due to printing on paper. Images used are for illustration purposes only. ADAS features are for driver assistance only. Driver is responsible for safe and attentive driving. Features may vary by models/ conditions. For details on functioning of safety features including airbags, kindly refer to the Owner's Manual. Trademarks/Logos being displayed belong to the respective owners. Infinity is the trademark of HARMAN International Industries Incorporated. Dolby, Dolby Audio, Dolby Atmos and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. \*Ex. Showroom price of ₹ 10,49,900 for Victoris LXI Petrol variant, Consumer offer (-) ₹ 20, Maximum Exchange Bonus (-) ₹ 30,000, Purchased Cycle Management (PCM) Bonus (-) ₹ 25,000, Upgrade Bonus (-) ₹ 20,000, ISL Offer (-) ₹ 10,000 = Effective price of ₹ 9,64,900. The PCM Bonus is applicable only in respect of cars that are up to (and including) six years old and may be availed only in the event of an exchange in combination with the applicable exchange bonus. The PCM Bonus cannot be combined with the scrappage bonus. Offer Valid only on Victoris LXI variant. The actual effective price mentioned may vary. Offers are subject to availability of stock, and valid till limited period. Maruti Suzuki India Limited reserves the right to discontinue offers without notice and offers may vary across variants. \*Fuel efficiency as certified by the Test Agency.